(ख) उम्मीदवारों के चयन के लिए कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा लगभग वही प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनायी जाती हैं ।

राज्यों में मद्य-निषेध

1953. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन में मद्य निषेध लागू किया गया था और बाद में समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार पूरे राष्ट्र में मद्य निषेध की नीति पर विश्वास करती है ; और

(ग) जिन राज्यों में मद्य निषेध लागू किया गया था उन में मद्य पान करने वाले व्यक्तियों की सख्या में कमी क्यों नहीं हो पाई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार सरकारों ने संबंधित राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया था । बिहार सरकार ने अलबत्ता राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध हटा दिया है ।

(ख) भारत सरकार संविधान में दी गई नीति के प्रति वचनबद्ध है ।

(ग) इस पर कोई टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्योंकि शराब के व्यवसनी व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

Apex Body for Housing Development Schemes

1954. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Centre has asked the States to set up an apex body of development authorities for better coordination in respect of housing development schemes;

(b) if so, whether many of the States have started implementing the suggestions;

(c) whether Union Territories were also asked to do the same;

(d) whether the Ministry feel that there was a shortage of two crore housing units in the country and three-fourth being in the rural areas;

(e) if so, the steps which are being taken in this regard; and

(f) whether both Centre and State Governments have agreed to build these and cover them during the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir. According to the estimate made by NBO, Housing shortage in the country in April 1980 was of the order of 20.7 million units, 4.6 million units in urban areas and 16.1 million units in rural areas.

(e) and (f). Housing is a state subject. Central Financial assistance is given in the States for the State Sector Programmes, including Housing, in the form of 'Block loans' and 'Block grants' without being tied to any particular scheme or head of development. As the housing problem